



2026:AHC:53946

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7489 वर्ष 2026

अनुज शर्मा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सौमित्र द्विवेदी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए., हरि केशव, शिवेन्द्र राज सिंघल

न्यायालय सं. - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री विवेक सरन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सौमित्र द्विवेदी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की सहायता सं, श्री धर्मेन्द्र सिंघल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि केशव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री आलोक शर्मा, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 761 वर्ष 2026 में बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन लोहियानगर, जिला-मेरठ की धारा- 318(4), 316(2), 336(3), 340(2), 338, 351(2), 352 के तहत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि पार्टियों के बीच विवाद विशुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति का है, क्योंकि आवेदक, उसके पिता और पहले सूचनाकर्ता का बेटा एफआईआर में उल्लिखित ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि पक्षकारों ने अब अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, और वर्तमान जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान उनके बीच एक लिखित समझौता/समझौता ज्ञापन किया गया है। इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने दो मामलों के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 17.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. पहले सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी स्वीकार किया कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, क्योंकि विवाद ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बीच था। विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और अवर न्यायालयों के समक्ष भीड़भाड़ वाली जेलों और आपराधिक मामलों के भारी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए साथ ही **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में रिपोर्ट किए गए **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जनादेश पर विचार

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- अनुज शर्मा को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति, संदर्भ में: स्वतः रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल)

मार्च 17, 2026

एसए

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"